शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020): उच्च शिक्षा में सुधारों पर एक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

डॉ. कंचन जैन, शिक्षा शास्त्रविभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

सार

किसी देश के लिए उसका उच्च शिक्षा स्तर पर अच्छी तरह से भविष्यवादी शिक्षा नीति आवश्यक है क्योंकि शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है। विभिन्न देश परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं और इसे प्रभावी बनाने के लिए अपने जीवन चक्र के दौरान उच्च शिक्षा स्तरों पर विभिन्न चरणों में सुधारों को अपनाते हैं। भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह प्रस्तुत शोध पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली में घोषित विभिन्न नीतियों पर प्रकाश डालता है और उनकी तुलना वर्तमान में अपनाई गई प्रणाली से करता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर एनईपी 2020 के विभिन्न नवाचारों और अनुमानित प्रभावों के साथ-साथ इसकी खूबियों पर भी चर्चा की गई है।

मुख्य शब्द - एनईपी 2020, स्कूल शिक्षा, सुधार,सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), उच्च शिक्षा विश्लेषण।

शोध उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में सुधारो का पता लगाना।

शोध प्रविधि नई शिक्षा नीति पर सरकारी रिपोर्ट एवं समाचार पत्रों का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

यह नीति प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। (बी.वेंकटेश्वरलू)। ऐसी नीति की शुरुआत के पीछे का विचार भारत में शिक्षा और सीखने की मौजूदा प्रणाली में अंतर को पाटना है। और इस अंतर को तभी पाटा जा सकता है, जब भारत में शिक्षा प्रणाली में नए सुधार शामिल किए गए हैं। यह एनईपी 2020 के माध्यम से किया गया है जहां फोकस क्षेत्र नवाचार, कौशल, समानता, सीखने में गुणवत्ता हैं। भारत जैसा कि एक देश उम्मीद कर रहा है कि वर्ष 2040 तक उसके पास एक अग्रणी शिक्षा प्रणाली होगी। वैश्वीकरण और बाजार के रुझान ने

शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

पहले से ही अनुकूली परिवर्तनों की भावना दी है जो ज़रूरत है। अब यह केवल ज्ञान और शिक्षा के बारे में नहीं है, जब भविष्य की भूमिकाओं के लिए छात्रों को आकार देने की बात आती है तो कौशल, नवाचार, बाजार की मांग पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, कम सामग्री की अवधारणा की ओर बढ़ने की जरूरत है, और अधिक सीखना. छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी और उनकी आलोचनात्मक सोच सिखाई जानी चाहिए। क्षमता का विकास करना चाहिए. शिक्षा को चरित्र का निर्माण करना चाहिए, शिक्षार्थियों को नैतिक, तर्कसंगत, दयालु और देखभाल करने में सक्षम बनाना चाहिए, साथ ही उन्हें लाभकारी के लिए तैयार करना चाहिए। एनईपी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। कोविड-19 के दौरान, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो एकमात्र सकारात्मक बात हुई, वह यह नीति थी जो भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने का वादा करती है। जैसा कि कहा जाता है, प्रकृति के नियम में परिवर्तन, लेकिन यह परिवर्तन 35 वर्षों से अधिक समय से लंबित था। पिछली बार हमने इसी क्षेत्र में ऐसा ही परिवर्तन देखा था।

इस गतिशील दुनिया में किसी भी चीज़ के जीवित रहने के लिए बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए भी यही बात लागू होती है, बदलती सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), औद्योगिक आवश्यकता के साथ इसकी आवश्यकता है हमारे सीखने के तरीके में बदलाव। और जैसा कि शिक्षा में वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, समग्र प्रणाली में एक आदर्श बदलाव देखा जा रहा है। भारत के लिए भी उस बदलाव को पकड़ना महत्वपूर्ण था, इस दिशा में एनईपी के माध्यम से एक प्रयास किया गया है। 2020 भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। अध्ययन पूरी तरह से गुणात्मक प्रकृति का है क्योंकि यह पूरी तरह से द्वितीयक डेटा स्रोतों पर निर्भर करता है।

भारतीय उच्च शिक्षा

भारत में, उच्च शिक्षा (एचई) के कई नियामक एचईआई के लिए एकल नियामक के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) में एकजुट होने जा रहे हैं। प्रमाणन निकाय जैसे (NAAC और NBA) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है और एक नई राष्ट्रीय प्रमाणन परिषद (NAC) बनाई जाएगी।

एनईपी यह भी बताती है कि सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों का नामांकन कैसे बढ़ाया जाए। भारत में GER चिंता का विषय रहा है; वर्तमान शिक्षा नीति में इस पर विशेष फोकस है। एनईपी समग्र और बहुविषयक शिक्षा पर जोर देती है। उच्च शिक्षा में दृष्टिकोण और अनुसंधान को अब केवल यूजी स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान नीति का तनाव खत्म हो गया है ।अंतर-विषयक और परिणाम आधारित शिक्षा के साथ एक छात्र का संपूर्ण विकास। शिक्षा के सभी स्तरों पर डिग्री प्राप्त करने में लचीलापन और एकाधिक प्रवेश-निकास विकल्प प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रस्ताव। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन

शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए या तो शुरू किया जाएगा या मौजूदा को नया रूप दिया जाएगा। पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण। छात्र केंद्रित शिक्षण और सीखने की पद्धति एनईपी में महत्वपूर्ण होगी। 2020 वर्तमान शिक्षक केंद्रित शिक्षण मॉडल के स्थान पर विकल्प आधारित से योग्यता आधारित में नया रूप दिया गया। मूल्यांकन और आकलन मॉडल है। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली से लेकर सतत मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव होने जा रहा है। सभी HEI को कौशल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्हें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए परामर्शदाताओं के साथ परामर्श केंद्रों का भी प्रावधान करना होगा। पारंपरिक शिक्षा बड़े पैमाने पर बदलाव की ओर जा रही है क्योंकि आगे से यह बाजार संचालित होगी। भारत सरकार का लक्ष्य विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना है।

और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है। विदेश में पाठ्यक्रम पूरा किया गया। छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा वेटेज दिया जाएगा और भारत में समकक्ष माना जाएगा। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार निधि को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाएगा। एनईपी ने बहु-विषयक को अनिवार्य किया है। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षा मॉडल। और इन संस्थानों के पास कम से कम 3000 की छात्र संख्या वाला एक परिसर होना चाहिए। बहु-बहु बनने के लिए प्रदान की गई समय सीमा अनुशासन 2030 है और 2040 तक उनके पास 3000 छात्रों की संख्या होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इन बहु-विषयक विश्वविद्यालयों को या तो अनुसंधान या शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनमें से एक में विशेष संस्थान बन सकते हैं। कॉलेजों को विकल्प दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में भारत में चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में सुधारात्मक कदम है

भारत की बेहतरी के लिए। नीति तैयार करने में बहुत प्रयास किए गए हैं, यह गहन शोध, विचार-विमर्श और चर्चा का परिणाम है कि हम कुछ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

एनईपी के रूप में व्यापक। लेकिन, इसके सफल कार्यान्वयन में कुछ बदलाव मौजूद हैं।

ये सुधार जो इस प्रकार है,इतने बड़े बदलावों को शामिल करने के लिए बुनियादी ढांचे और धन की कमी है

प्रणाली में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता और गतिशीलता पर जोर देकर भारत को शिक्षा के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। नीति शिक्षा क्षेत्र में व्यय को जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन आंकड़े बेहद सिकुड़ती तस्वीर पेश करते हैं. यह पहली बार नहीं है

शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

कि शिक्षा में निवेश बढ़ाने की बात हो रही है. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का कहना है कि भारत इसके बाद भी शिक्षा क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का केवल 3.1% खर्च करता है। तो पहली बात यह है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

प्रेस सूचना ब्यूरो ने बताया कि 1 अगस्त 2022 को, *"यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस"* (UDISE+) 2020-21 के अनुसार, ग्रेड (1-5) में शिक्षण और सीखने में 28 से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाना है। भाषाएँ असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मैतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत हैं ।सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, बोडो, खासी, गारो, मिजो, फ्रेंच, हमार, कार्बी, संथाली, भोडी और पुर्गी । [6] [7] नई शिक्षा नीति सामान्य फार्मूले (5+3+3+4) पर आधारित है। यह छात्र पर आधारित है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं है।

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि एनईपी 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एनईपी 2020 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को 2022 तक चरणों में लागू किया जाएगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारत की शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख पड़ाव

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) का ध्यान प्राथमिक विद्यालय के बाद और विश्वविद्यालय शुरू होने से पहले की शिक्षा पर था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) को 'राधाकृष्णन आयोग' के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन) उच्चतर शिक्षा पर केंद्रित थे,शिक्षा आयोग (1964-66) के नाम से भी जाना जाता है। 'कोठारी आयोग', क्योंकि इसका नेतृत्व डॉ. डी.एस. ने किया था। कोठारी आयोग का दृष्टिकोण समग्र था। प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक का चरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968: कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक नीति की घोषणा की जिसमें समानता का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने के लिए शैक्षिक अवसर एकीकरण और अधिक से अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास और 42वां संवैधानिक संशोधन, 1976, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ताकि राज्यों के साथ-साथ संघ भी इस पर विचार कर सके। सरकार पहले यह राज्य सूची में थी, जिससे कानून बनाने के मामले में राज्य सरकारों को

शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

प्राथमिकता मिलती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसका उद्देश्य "निकालने पर विशेष जोर" था। असमानताओं और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने के लिए,"विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के लिए। 1986 का एनपीई 1992 में संशोधित किया गया था। द्वारा अपनाया गया 'सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम' शिक्षा (आरटीई) अधिनियम पारित किया गया, जिसने प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट 2016 ने कार्यान्वयन अंतराल को संबोधित करके शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने की मांग की।एनईपी 2020 ने हमें उच्च शिक्षा को अर्थव्यवस्था के अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने वाला इंजन बनाने के लिए संपूर्ण प्रणाली की पुनर्कल्पना, पुन: पुनर्गठन करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए, हम खुद को नई संभावनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं, लेकिन बीच का अंतर नीति और कार्यान्वयन ऐतिहासिक रूप से काफी व्यापक और गहरा रहा है।

शोध परिणाम

हम उन कई देशों से पीछे रह जाएंगे जो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रगति पर काम कर रहे हैं और लगातार नई ऊंचाइयां हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। शैक्षिक क्षेत्र में. कुछ सुझाव जो एनईपी के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान दे सकते हैं वे हैं: इसमें शामिल सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। नीति का सफल कार्यान्वयन केंद्र सरकार, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय इस नीति को सफल बनाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। माता-पिता, छात्रों, उद्योग से समय पर प्रतिक्रिया भी सफल होने में मदद करेगी। नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन शिक्षकों के प्रशिक्षण और आवश्यक कौशल विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें छात्रों के लिए भी यही बात लागू होती है। इस नीति को बनाने के लिए शिक्षा की ओर अधिक निवेश किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

एनईपी 2020 एक ऐसी नीति है जिसे प्रस्तुत करने में बहुत आशा और आशावाद देखा गया है। देश की समग्र शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। पुरानी शिक्षा उदाहरण के लिए, आधुनिक समय में प्रणाली और प्रथाओं की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। हमने कोविड-19 के दौरान देखा है कि आईसीटी को भारत का सक्रिय हिस्सा बनाना कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, और एक देश के रूप में हमें अपने छात्रों और शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है सीखने की समग्र प्रक्रिया को अधिक समृद्ध और संतोषजनक बनाने के लिए इस कौशल को सीखना। पुरानी शिक्षा प्रणाली को जारी रखना अर्थहीन हो गया है। सरकार को उच्च शिक्षा के

शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

पाठ्यक्रम में बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। शिक्षा कुशल जनशक्ति प्राप्त करने की वैश्विक मांग को अवशोषित कर रही है। जिससे नई शिक्षा नीति 2020 धरातल पर खरी उतरे।

संदर्भित ग्रंथ सूची

- विश्नोई, अनुभूति (31 जुलाई 2020)। "एनईपी '20: एचआरडी के साथ अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा माध्यम में कोई बदलाव नहीं"। *द इकोनॉमिक टाइम्स*। 15 जुलाई 2021 को मूल सेसंग्रहीत। 31 जुलाई 2020
- गोहेन, मानश प्रतिम (31 जुलाई 2020)। "एनईपी भाषा नीति व्यापक दिशानिर्देश: सरकार"। *टाइम्स ऑफ इंडिया*। 31 जुलाई 2020 को मूल सेसंग्रहीत। 31 जुलाई 2020
- चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020)। "समझाया: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना" । *इंडियन एक्सप्रेस*। 1 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत ।
- "मातृभाषा में शिक्षा" । *www.pib.gov.in/ _* 23 जनवरी 2023 को मूल से संग्रहीत । 23 जनवरी 2023 को लिया गया ।
- *pib.gov.in* (मणिपुरी में)। 23 जनवरी 2023 को मूल से संग्रहीत । 23 जनवरी 2023 को लिया गया ।
- ^ चतुर्वेदी, अमित (30 जुलाई 2020)। "' परिवर्तनकारी ' : नेताओं, *शिक्षाविदों* ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत किया ।
- "कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाला पैनल स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करेगा" । Indianexpress.com. 22 सितंबर 2021। 16 अक्टूबर 2021 को मूल से संग्रहीत । 16 अक्टूबर 2021 को लिया गया ।
- "राज्य शिक्षा बोर्डों को राष्ट्रीय निकाय द्वारा विनियमित किया जाएगा: ड्राफ्ट एनईपी" । *टाइम्स ऑफ इंडिया* । 30 अक्टूबर 2019. 27 फरवरी 2021 को मूल से संग्रहीत । 21 नवंबर 2019 को लिया गया ।
- "यहां बताया गया है कि आप नई एनईपी पर खुशी क्यों मना सकते हैं। और आप क्यों नहीं मना सकते" । *तार* . 31 जुलाई 2020. 1 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत ।
- जेबराज, प्रिसिला; हेब्बार, निस्तुला (31 जुलाई 2020)। रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं, "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने से पहले किया गया कठोर परामर्श" ।
- *द हिंदू*। आईएसएसएन 0971-751X . 6 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत । .

शब्दसागर
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, रेफर्ड, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN (O) : 2584-2889
वर्ष 1, अंक 3, अप्रैल - जून 2024
Online Available : https://shabdasagar.in/

- ^ रोहतगी, अनुभा, एड. (7 अगस्त 2020)। "मुख्य बातें | एनईपी भारत में अनुसंधान और शिक्षा के बीच अंतर को कम करने में भूमिका निभाएगी: पीएम मोदी" । *हिंदुस्तान टाइम्स*। 9 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत। 8 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त .
- "सरकार ने शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी" । *लाइवमिंट*। 29 जुलाई 2020. 8 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत। 30 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त .
- "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी: मुख्य बिंदु" । *टाइम्स ऑफ इंडिया*। 29 जुलाई 2020. 29 जुलाई 2020 को मूल से संग्रहीत। 29 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त .
- "कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 10 अंक" । *एनडीटीवी.कॉम*। 30 जुलाई 2020 को मूल से संग्रहीत। 30 जुलाई 2021 को लिया गया।
- "कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, जिससे देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा" । *pib.gov.in*। 8 अगस्त 2021 को मूल से संग्रहीत। 8 अगस्त 2021 को लिया गया।
- "शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन लॉन्च किया" । *@बिजनेसलाइन*। 5 जुलाई 2021. 8 अगस्त 2021 को मूल से संग्रहीत। 8 अगस्त 2021 को लिया गया।
- ऊपर जायें:[ए बी सी डी ई] श्रीनिवासन, चन्द्रशेखर, एड। (29 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020: कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई: नई शिक्षा नीति पर 10 बिंदु"। एनडीटीवी. 29 जुलाई 2020 को मूल सेसंग्रहीत। 29 जुलाई 2020को पुनःप्राप्त.
- कुलकर्णी, सागर (29 जुलाई 2020)। "नई नीति स्कूली शिक्षा का 5-3-3-4 मॉडल पेश करती है" । *डेक्कन हेराल्ड*। 1 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत। 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त .